

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 मई 2017—वैशाख 14, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

भोपाल, दिनांक 4 मई 2017

क्र. एफ 87-195-15-11-63.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014” म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-7-2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह-दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, माचलपुर, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री दिनेश कुमार भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 04/12/2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03/01/2015 तक श्री दिनेश कुमार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म.प्र.) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 459, दिनांक 07/02/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री दिनेश कुमार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 23/1/15 अर्थात् 20 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री दिनेश कुमार को आयोग की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27/3/15 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस

में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की रिपोर्ट उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला-राजगढ़ के पत्र दिनांक 05/1/2016 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग के ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा जिले से इस बात की जानकारी चाही गई कि नोटिस तामीली के उपरांत अभ्यर्थी, श्री दिनेश कुमार द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में कोई जबाब प्रस्तुत किया गया हो तो अभिमत सहित आयोग को अवगत कराया जाये।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था. निर्वा.), जिला-राजगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/2/2017 में इस बात की जानकारी आयोग को दी गई कि अभ्यर्थी श्री दिनेश कुमार द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के उपरान्त जिला स्तर पर अपने निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में कोई जबाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही अनुशंसा की गई कि इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जाये।

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त श्री दिनेश कुमार के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 10/3/17 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 18/4/2017 को बुलाया गया।

अभ्यर्थी श्री दिनेश कुमार को सूचना-पत्र तामीली की रिपोर्ट उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला-राजगढ़ के पत्र दिनांक 11/4/17 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो गई थी, पर अभ्यर्थी श्री दिनेश कुमार व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 18/4/2017 को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्री दिनेश कुमार द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी, श्री दिनेश कुमार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् माचलपुर, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 4 मई 2017

क्र. एफ 87-195-15-11-64.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014” म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-7-2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह-दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, माचलपुर, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री गुलाब बाई भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 04/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03/01/2015

तक सुश्री गुलाब बाई को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म.प्र.) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 459, दिनांक 07/02/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री गुलाब बाई द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी, सुश्री गुलाब बाई को आयोग की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27/3/15 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की रिपोर्ट उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला-राजगढ़ के पत्र दिनांक 05/1/2016 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग के ज्ञापन दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा जिले से इस बात की जानकारी चाही गई कि नोटिस तामीली के उपरान्त अभ्यर्थी, सुश्री गुलाब बाई द्वारा अपने निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत किया गया हो तो अभिमत सहित आयोग को अवगत कराया जाये।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था. निर्वा.), जिला-राजगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/2/2017 में इस बात की जानकारी आयोग को दी गई कि अभ्यर्थी सुश्री गुलाब बाई द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के उपरान्त जिला स्तर पर अपने निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में कोई जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही अनुशंसा की गई कि इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जाये।

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त सुश्री गुलाब बाई के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 10/3/17 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 18/4/2017 को बुलाया गया।

अभ्यर्थी, सुश्री गुलाब बाई को सूचना-पत्र तामीली की रिपोर्ट उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला-राजगढ़ के पत्र दिनांक 11/4/17 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो गई थी, पर अभ्यर्थी सुश्री गुलाब बाई व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 18/4/2017 को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, सुश्री गुलाब बाई द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किया गये। अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी, सुश्री गुलाब बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् माचलपुर, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2017

क्र. एफ 87-204-15-11-67.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014” म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10-7-2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह-दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, सुठालिया, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री गोपाल सिंह भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07/12/2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06/01/2015 तक, श्री गोपाल सिंह को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म.प्र.) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 459, दिनांक 07/02/15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री गोपाल सिंह द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दिनांक 02/02/15 अर्थात् 26 दिन विलम्ब से दाखिल किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री गोपाल सिंह को आयोग की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27/3/15 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरान्त जिले से आयोग के पत्र दिनांक 11/05/15 द्वारा यदि अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदनादि प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी विश्वसनीयता/स्वीकार्यता बावत् स्पष्ट अभिमत चाहा गया।

इस सम्बन्ध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला-राजगढ़ के ज्ञापन दिनांक 561, दिनांक 27/2/2017 के संलग्न कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ के आयोग के पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 221, दिनांक 02/7/2016 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु आयोग को भेजी गई। कलेक्टर, राजगढ़ के पत्र में इसी बात का उल्लेख था कि अभ्यर्थी, श्री गोपाल सिंह 26 दिन विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया।

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री गोपाल सिंह के विलम्ब से प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ के माध्यम से नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 18/4/2017 को बुलाया गया।

अभ्यर्थी श्री सिंह को जारी उपर्युक्त सूचना-पत्र व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व तामीली होने की सूचना उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था. निर्वाचन) जिला राजगढ़ के ज्ञापन 11/4/2017 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो गई थी।

अभ्यर्थी श्री गोपाल सिंह को नोटिस तामीली की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी वे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तय तिथि दिनांक 18/4/2017 को उपस्थित नहीं हुए और न ही अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, श्री गोपाल सिंह द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस विलम्ब के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई। अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी, श्री गोपाल सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् सुठालिया, जिला-राजगढ़ (म.प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (आयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.